भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 316
दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ

पंचायत स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वित्तीय सहायता

316. डॉ आलोक कुमार सुमन:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायत स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बिहार राज्य, विशेषकर गोपालगंज जिले को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो पंचायत स्तर पर प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु कुल कितनी राशि प्रदान की गई है और कुल कितनी राशि अभी प्रदान की जानी शेष है;

(ग) क्या सरकार और अधिक विकास के लिए पंचायतों और केन्द्रीय मंत्रालयों को कम्प्यूटरों के माध्यम से जोड़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पंचायतों के प्रौद्योगिकीय विकास के लिए बिहार के गोपालगंज जिले में कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ङ): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। मंत्रालय ने पंचायत के काम जैसे आयोजना, लेखांकन और बजटन को सरल बनाने के लिए एक लेखांकन एप्लीकेशन ई-ग्रामस्वराज शुरू किया है, साथ ही जमीनी स्तर पर बेहतर शासन हेतु पंचायतों के लिए ऑडिटऑनलाइन एप्लीकेशन, मेरी पंचायत ऐप, पंचायत निर्णय ऐप, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल आदि जैसे अन्य ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू किए हैं। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों (जीपी) को विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी एकीकृत किया है।

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कंप्यूटरों की खरीद के लिए सीमित पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। निधि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है, न कि जिले को। चालू वित्त वर्ष अर्थात वर्ष 2024-25 के दौरान, बिहार की ग्राम पंचायतों के लिए 267 कंप्यूटरों की खरीद के लिए 1.335 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके

अलावा, एक विशेष हस्तक्षेप के रूप में चालू वित्त वर्ष के दौरान 15.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त 2000 कंप्यूटरों की खरीद को भी मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

ई-एमएमपी परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित ऑनलाइन एप्लीकेशनों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर डिजिटल शासन स्थापित करना तथा पंचायतों को केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकार के विभागों सहित अन्य संस्थानों के साथ एकीकृत करना है।

परियोजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है। ई-पंचायत परियोजना के तहत विकसित सॉफ्टवेयर/ऑनलाइन-एप्लीकेशन/ऐप के विकास/रखरखाव के लिए एनआईसी को धनराशि जारी की जाती है। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना पर वर्षवार वार्षिक व्यय **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

'पंचायत स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 316 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना पर वार्षिक व्यय का विवरण

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2020-21	20	17.82	17.79
2021-22	20	11.71	11.71
2022-23	20	15	15
2023-24	20	16.28	16.03
2024-25	90.17	34	9.75*

जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार